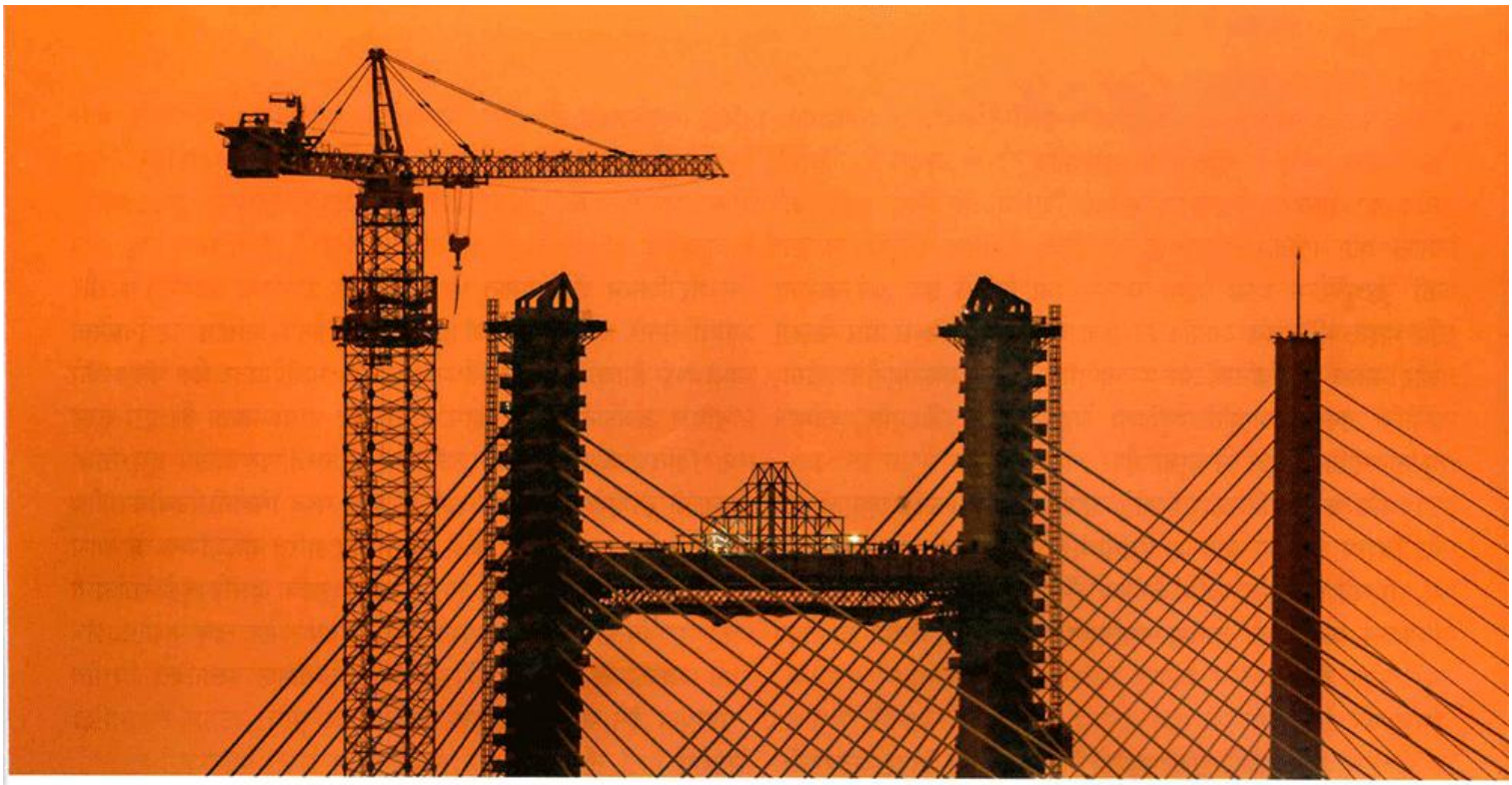

राजकोषीय माध्यम से भारत में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना

डॉ अमिय कुमार महापात्र | प्रोफेसर एवं डीन ऑफ रिसर्च, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंदौर।
ईमेल: amiyacademics@gmail.com.

भारत, जनसांख्यिकीय लाभांश के मामले में विलक्षण स्थिति में है, जिसमें लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या युवाओं (18-35 वर्ष) की और 62 प्रतिशत से अधिक 15-59 वर्ष के आयु वर्ग की है, जिसकी 2035 तक बढ़कर 65 प्रतिशत तक होने की आशा है। भारत के इस जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ, एकीकृत विकास के लिए पर्याप्त कार्यनीतिक उपाय करने, जनसंख्या को सामान्य रूप से उत्पादक तथा समृद्ध बनाने और विशेष रूप से आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे के विकास की मदद से उठाया जा सकता है। बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अनिश्चित तथा चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बीच वृद्धि और विकास प्रक्रिया को बनाए रखने में एक प्रमुख वाहक के रूप में कार्य करता है। बुनियादी ढांचे में निवेश के प्रभावों में अर्थव्यवस्था के विकास, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, क्षेत्रीय तथा संतुलित विकास, सकारात्मक सामाजिक प्रभाव और नवाचार तथा प्रौद्योगिकी एकीकरण के माध्यम से समावेशी, आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना शामिल है। यह एक तथ्य है कि बुनियादी ढांचे के स्वाभाविक रूप से तीव्र विकास से कुछ पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेंगे और राष्ट्र के लिए चुनौतियां पैदा होने की संभावना है। अतः इस स्थिति से निपटने और लोगों, समाज तथा ग्रह की भलाई को ध्यान में रखते हुए हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाएं समय की मांग है।

भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उसकी नीतिगत रणनीति के नियोजित विकास के लिए परिवर्तकारी विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण महत्वपूर्ण है। इसमें भौतिक, सामाजिक, वित्तीय तथा डिजिटल बुनियादी ढांचा शामिल है। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया कि निवेश खर्च में 1 प्रतिशत की वृद्धि भारत में सकल घरेलू उत्पाद को 1.0 से बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत तक कर सकती है, जिसका सीधा प्रभाव रोज़गार सृजन और सतत विकास पर पड़ता है। इसके अलावा, यह भी पाया गया है कि परिवहन, ऊर्जा तथा शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश उनके अधिक गुणक प्रभावों के कारण व्यवस्थित और तेज गति से विकास को बढ़ावा देता है। जाहिर है, वित्त वर्ष 2024-25 के मौजूदा बजट में आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति पर उनके दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करते हुए इन क्षेत्रों और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों के लिए धन आवंटित किया गया है।

प्रमुख बुनियादी ढांचा पहल और आवंटन 2024-25

कुल बजटीय व्यय 48,20,512 करोड़ रुपये में से कुल पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 16.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह बजट प्रावधान सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत है, जो पिछले कुछ दशकों में अब तक का सबसे अधिक है। मजबूत राजकोषीय समर्थन और आवंटन के माध्यम से पिछले पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में वृद्धि दर्ज की गई है। प्रभावी पूंजीगत व्यय 15,01,889 करोड़ रुपये है, जो दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति सुनिश्चित करता है। यह वर्तमान जरूरतों को पूरा करने और तेजी से विकसित हो रहे भारत की भविष्य की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार की सकारात्मक मंशा को दर्शाता है। पिछले पांच वर्षों के बुनियादी ढांचे पर निवेश के लिए आवंटन में लगातार प्रगति दिखाई देती है। यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने में सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ता को दर्शाता है।

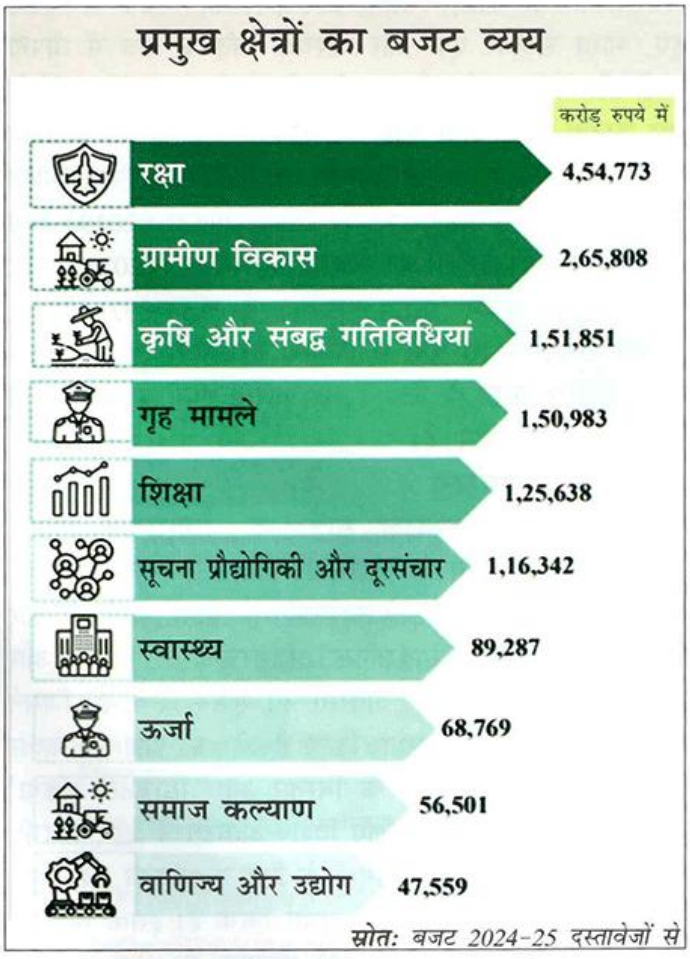

चित्र 1: विभिन्न क्षेत्रों का बजट परिव्यय

भौतिक संपर्क अवसंरचना

भारत में भौतिक संपर्क और अवसंरचना विकास को बढ़ाने के लिए बजट प्रावधानों में सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों और बंदरगाहों में निवेश शामिल है, जिसका उद्देश्य एक मजबूत, एकीकृत और पारस्परिक रूप से सहायक परिवहन व्यवस्था का निर्माण करना है।

सड़क मार्ग: सड़क नेटवर्क के उन्नयन ने परिवर्तनशील और कुशल बुनियादी ढांचे को जन्म दिया है जो आर्थिक अवसरों, संपर्क, पर्यटन और शहरीकरण को बढ़ावा देता है। इस क्षेत्र ने उल्लेखनीय रूप से सबसे अधिक निजी निवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण को आकर्षित किया है। सड़क विकास में नए जमाने की तकनीक और टिकाऊ कच्चे माल का उपयोग शामिल किया गया है। 'भारतमाला परियोजना' के तहत, भारत सरकार का लक्ष्य कनेक्टिविटी बढ़ाने और माल ढुलाई को तेज करने के लिए देश भर में सड़क नेटवर्क बनाना है, जिससे लॉजिस्टिक लागत को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, सरकार की योजना पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव के साथ सड़क मार्ग को दो-लाइनों में करने की है। सड़क संपर्क को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए, पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया-दरभंगा एक्सप्रेसवे और गंगा पर 2-लेन पुल के लिए 26,000 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। देश भर में मजबूत सड़क नेटवर्क बनाने के लिए सड़कों और राजमार्गों के निर्माण के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

रेलवे: भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क समेटे हुए है। रेलवे क्षेत्र में काफी अधिक निवेश किया जा रहा है, क्योंकि यह लोकोमोटिव और वैगनों दोनों के लिए अधिकतम उत्पादन के साथ विभिन्न अवसरों को खोलता है। सरकार के द्वारा रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में स्वच्छता प्रदान करने के लिए कई पहल की गई हैं, जिसमें स्टेशनों और कोचों के आसपास बायो-टॉयलेट का निर्माण शामिल है। यातायात गलियारों, ऊर्जा

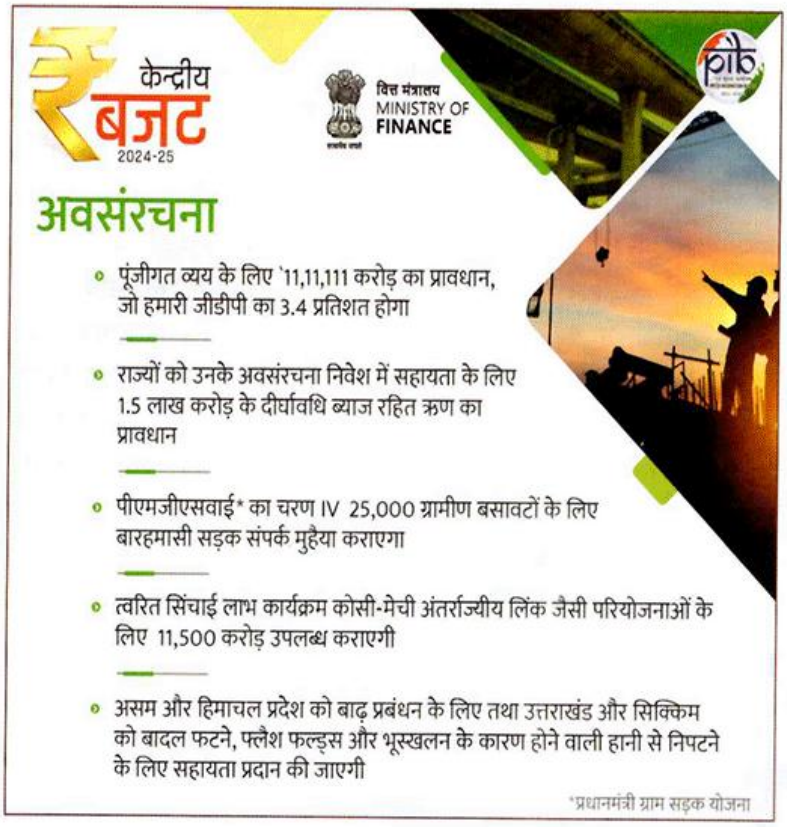

गलियारों, खनिज तथा सीमेंट गलियारों और रेल सागर गलियारों जैसे संवर्द्धन के क्षेत्रों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य मुख्य रूप से अक्षय ऊर्जा के माध्यम से कार्बन को कम करना है। बजट 2024-25 में, रेलवे विकास के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है, और इससे विकास पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

जलमार्ग: आर्थिक विकास को बढ़ाने और स्थायी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, स्मार्ट जल प्रौद्योगिकी तथा बुनियादी ढांचे में निवेश, बढ़ते व्यापार को पूरा करने और वैश्विक क्षेत्र में भारत की समुद्री प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में मदद करता है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं की बढ़ती संख्या ने 'पीएम गति शक्ति' राष्ट्रीय मास्टर प्लान और 'सागरमाला' राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ाया है। इसके अलावा, बंदरगाह आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी, बंदरगाह-आधारित औद्योगीकरण, तटीय समुदाय तथा अंतर्देशीय जल परिवहन में और विकास कार्य किए जा रहे हैं।

वायुमार्ग: विमानन क्षेत्र में निवेश वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है। सरकार ने समूचे भारत में हवाई अड्डों के विकास, उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2025 की अवधि के लिए 26,000 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया है। विमानों को पट्टे पर देने और शिक्षा, कृषि, आपदा प्रबंधन तथा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में लाभ प्रदान करने वाले ड्रोन के उपयोग के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं।

कुल मिलाकर, 'पीएम गति शक्ति' योजना बुनियादी ढांचे की कार्यनीति का एक हिस्सा होने के नाते, एक अधिक परस्पर जुड़ी बुनियादी ढांचा प्रणाली बनाने का लक्ष्य रखती है। भारत में विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी निकायों के बीच विभिन्न प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और समन्वय में सुधार करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप रसद दक्षता में सुधार होता है, लागत में कमी आती है और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी आती है। इसका अंतिम उद्देश्य एकीकृत बुनियादी ढांचा नियोजन और समय पर प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से बुनियादी ढांचा क्षेत्र में दक्षता बढ़ाना है।

अंतरिक्ष अवसंरचना

भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विशेष रूप से इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (पीएसएलवी), जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (जीएसएलवी), लॉन्च व्हीकल मार्क-3 (एलवीएम3) और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (एसएसएलवी) सहित कई विमानों के प्रक्षेपण में अग्रणी भूमिका निभाई है। अंतरिक्ष अवसंरचना के लिए विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार एक ओर वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और दूसरी ओर कई सफल मिशनों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा तथा वैज्ञानिक कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए उत्सुक है। कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों में मार्स ऑर्बिटर मिशन (2014), एस्ट्रोसैट (2015), चंद्रयान-2 ऑर्बिटर (2019) तथा उसके बाद, चंद्रयान-3 का चंद्रमा पर लैंडिंग (2023) और आदित्य-एल1 मिशन (2023) शामिल हैं। बजट 2024-25 में, सरकार ने अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना तक विस्तारित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये के उद्यम पूंजी कोष का प्रस्ताव दिया है।

डिजिटल अवसंरचना

एक मजबूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना निवेश, निश्चित रूप से भारत के 'डिजिटल इंडिया', 'फिनटेक नेशन' और 'स्टार्टअप इंडिया' के उद्देश्यों को प्राप्त करने के द्वार खोलता है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण और विस्तार में निवेश ने अपार अवसरों का सृजन किया है, जिसने लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है और कल्याण को बेहतर बनाया है। ब्रॉडबैंड नेटवर्क के विस्तार और 'डिजिटल इंडिया' पहल को मजबूत करने के लिए विशेष आवंटन ने आम आदमी, नागरिकों, एमएसएमई और निगमों के लिए प्रौद्योगिकी तक पहुंच सहित डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार किया है। इसके अलावा, शहरी नियोजन, ऊर्जा प्रबंधन और परिवहन के क्षेत्रों में स्मार्ट

प्रौद्योगिकियों को अपनाना अधिक कुशल और टिकाऊ पाया गया है। इन गुणक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने बजट में इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किया है और नीतिगत ढांचे के माध्यम से एकीकृत विकास को मजबूत करना जारी रखा है। उदाहरण के लिए, डिजिटीकरण और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्षेत्रों के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है।

भारत सरकार ने पीएम गतिशक्ति, भुवन, भारतमैप्स, सिंगल विंडो सिस्टम, परिवेश पोर्टल, नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति), इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड (आईआईजी) आदि जैसी कई कुशल बुनियादी ढांचा योजनाएं शुरू की हैं। एक सर्वविदित तथ्य के रूप में, डिजिटल बुनियादी ढांचे को दक्ष बनाने वाला समयानुकूल और सटीक संचार नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और शहरी-ग्रामीण प्रवास को कम करने में महत्वपूर्ण सफलता का कारक है। ये सभी कार्य भारतनेट परियोजना के तहत किए जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के साथ, सरकार 'भारत में एआई और भारत के लिए एआई' के तहत समावेश, नवाचार और सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए एआई (कृत्रिम मेधा) को शामिल कर रही है।

ऊर्जा अवसंरचना

बिजली क्षेत्र: एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, अधिकतम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके ट्रांसमिशन ग्रिडों के संवर्द्धन और बिजली उत्पादन के माध्यम से देश के बिजली क्षेत्र को आगे बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। संशोधित प्रेषण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए आवंटित बजट 3.04 लाख करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-वित्त वर्ष 2026) है, जिसमें अतिरिक्त 0.98 लाख करोड़ रुपये सरकारी सहायता है। इसका उद्देश्य वित्त वर्ष 2025 तक कुल तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे को कम करना है। इस क्षेत्र में 'एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड पहल', स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम, 'समर्थ मिशन' आदि जैसे कार्यक्रमों के तहत ऊर्जा-कुशल स्ट्रीट लाइट और पंखों के साथ ग्रिड आपूर्ति बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किया गया।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र: ऊर्जा के अधिक उपयोग और इसके परिणामों के प्रभाव को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य-2030 को पूरा करने के वास्ते ऊर्जा बुनियादी ढांचे के लिए राशि आवंटित की जाती रही है। चूंकि इस क्षेत्र में निवेश करने से आर्थिक विकास, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, जीवन स्तर में सुधार और सतत विकास को बढ़ावा देने के विभिन्न अवसर खुलते हैं। इसके बुनियादी ढांचा विकास में इस पर निर्भर विभिन्न क्षेत्रों के साथ सहसंबंध और उनका विकास भी शामिल होता है। इस क्षेत्र से 2024 और 2030 के बीच भारत में 30.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है, जिसमें देश के, पारंपरिक स्रोतों से गैर-जीवाश्म ईंधन के उपयोग की ओर बढ़ने की आकांक्षा है।

अन्य बुनियादी ढांचा पहल

भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए लगभग 2.66 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जो पिछले वर्ष के बजट से लगभग 12 प्रतिशत अधिक है। 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए तीन करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण की घोषणा की गई है। 'प्रधानमंत्री आवास योजना' (शहरी 2.0) के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। इसमें अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चरण-4 की शुरुआत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए की जाएगी। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए 11,500 करोड़ रुपये की लागत से वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है, जिसमें 'कोसी-मेची इंट्रा स्टेट लिंक' और 20 अन्य सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। सरकार ने

देश के पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए 'पूर्वोदय' नामक योजना तैयार की है, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इसमें मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसरों को खोलना शामिल होगा, ताकि इस क्षेत्र को 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने का वाहक बनाया जा सके।

सामाजिक बुनियादी ढांचे को हमेशा की तरह बजट आवंटन में विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि इससे जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक प्रगति में सुधार होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं ने राष्ट्र के समग्र कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बजटीय समर्थन प्राप्त करने वाली प्रमुख पहलों में आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अमृत योजना, समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय आजीविका मिशन आदि शामिल हैं। विभिन्न शोध अध्ययनों से पता चला है कि स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा तथा गवर्नेंस में निवेश का अधिक गुणक प्रभाव होता है और जीवन की गुणवत्ता पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उल्लेखनीय है कि सामाजिक पहल के रूप में, 'जन धन योजना-आधार-मोबाइल (जेएएम)' ट्रिनिटी पहल के माध्यम से 2013 से 38 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।

विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उचित सुविधाओं के साथ सही स्थानों पर औद्योगिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को पहचाना है। निजी क्षेत्र और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी के माध्यम से 100 शहरों में या उसके आसपास सभी प्रकार के बुनियादी ढांचे के साथ निवेश के लिए तैयार 'प्लग एंड प्ले' औद्योगिक पार्क बनाने का एक और प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास (एनआईसीडी) कार्यक्रम के तहत 12 नये औद्योगिक पार्क प्रस्तावित हैं। बजट में पूंजीगत आवश्यकताओं को अनुकूलित करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश में अधिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण को लागू करने और नीति तथा विनियमन का समर्थन करने का प्रस्ताव दिया है। निजी वित्त को आकर्षित करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बाजार आधारित वित्तीय ढांचा बनाया जाएगा। राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संसाधन आवंटन का समर्थन करने के लिए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इससे पूरे भारत में संतुलित विकास में योगदान मिलने की आशा है।

आगे की राह और 2047 तक भारत का भविष्य

बुनियादी ढांचे पर खर्च में वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत की विकास यात्रा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में नया मोड़ लेगी; और 'विकसित भारत-2047' तक भारत को 'विकसित राष्ट्र' बनाने में मदद करेगी, जो पूर्ण रूप से समग्र और सतत विकास का वादा करती है। सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पर्याप्त निवेश के प्रावधान किए हैं, क्योंकि यह आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण वाहक है। बुनियादी ढांचे पर खर्च और सकल घरेलू उत्पाद के बीच सकारात्मक सहसंबंध, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में राजकोषीय समेकन उद्देश्यों और लक्ष्यों से समझौता किए बिना बुनियादी ढांचे के प्रावधान में वृद्धि को रेखांकित करता है।

कुल मिलाकर, बजट मुख्य रूप से प्राथमिकताओं के 9 स्तंभों के विकास पर केंद्रित है, और बुनियादी ढांचा उनमें से एक है। बुनियादी ढांचे के लिए बजट में बड़ी राशि आवंटित की गई है। तेजी से आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति शुरू करने के लिए निरंतर और कार्यनीतिक प्रयासों पर ज़ोर दिया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में युवाओं के लिए विभिन्न अवसरों के सृजन के वास्ते कई प्रावधान किए गये हैं और सामाजिक सेवा प्रावधानों को भी बढ़ाया गया है। निजी क्षेत्र को शामिल करने और उन्हें बुनियादी ढांचे के विकास का हिस्सा बनाने के लिए, सरकार ने व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण, कर सुधार और बाजार वित्तपोषण में सुगमता की शुरुआत की है। ये उपाय न केवल निजी निवेश को आकर्षित करेंगे बल्कि समग्र बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को भी आकर्षित करेंगे, जिसका भारत की समग्र विकास कहानी पर कई गुना अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

यह एक तथ्य है कि स्वाभाविक रूप से बुनियादी ढांचे के तेजी से विकास से कुछ पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेंगे और राष्ट्र के लिए चुनौतियां पैदा होने की संभावना है। इसलिए, जन समाज के हित तथा पृथ्वी के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं समय की मांग हैं। इसके अलावा, नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संवर्धित बुनियादी ढांचागत बजट के परिणामस्वरूप सामाजिक-आर्थिक विकास के लाभ निचले तबकों और अंतिम छोर तक नागरिकों तक पहुंचें। यह सार्वजनिक नीतिगत पहल और सुशासन से सुनिश्चित किया जा सकता है। दीर्घकालिक राष्ट्रीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ये प्रभावी, समावेशी, सहयोगात्मक और टिकाऊ होने चाहिए। इन बहुविध लेकिन विकासोन्मुख उपायों के साथ, भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने के लिए आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वह वैश्विक रुझानों के अनुरूप प्रयास करता है और 'समग्र तथा सतत विकास एजेंडा' पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता है। ❑

(इस लेख में व्यक्त किए गए लेखक के विचार निजी हैं)

संदर्भ

- आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, भारत सरकार।
- केंद्रीय बजट दस्तावेज 2019 से 2024, भारत सरकार।
- केंद्रीय बजट 2024-25 पर विश्लेषण के साथ समाचार पत्र कवरेज।